

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार, सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

, जिलाधिकारी, चमोली।

राजस्व अनुभाग—2 देहरादूनः दिनांक 1 प फरवरी 2012 विषयः—मृदा परीक्षण प्रयोगशाला हेतु 0.086 है0 निःशुल्क भूमि हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-6899 / छब्बीस-एम0बी० (2009-10) दि0-23.7.2011 के संदर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, ग्राम क्षेत्रपाल (चमोली), जिला चमोली में 0.086 है0 भूमि मृदा परीक्षण प्रयोगशाला हेतु कृषि विभाग, उत्तराखण्ड को, वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260 / वित्त अनुभाग-3 / 2002 दिनांक-15.02.02 में निहित प्राविधानों एवं प्रशासकीय विभाग, उत्तराखण्ड शासन की प्राप्त सहमति के दृष्टिगत तथा आपके द्वारा संस्तुत / अनुमोदित खाता सं0-66 के खसरा नं0-1523 रकबा 0.073 है0 तथा खाता सं0-64 के खसरा संख्या-1534 रकबा 0.013 है0 भूमि को निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अनुसार, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड को निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमित प्राप्त हो चुकी है।
- 3— हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4— यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- 5— जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमित के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 6— जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

....

7— प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु, तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीध्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय, (कुँवर राजकुमार) सचिव।

पृ<u>0प0संख्या— 3 प्रार्थित वित्र / 2012</u> प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

3- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।

4-/ निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय।

5- प्रभारी, मीडिया केन्द्र, सचिवालय।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी) अनुसचिव।